उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 9 | 1-15 मई 2025 | ₹ 20/-

भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम उर्दू प्रेस की नजर में

- पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई
- बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तीन अरब देशों की यात्रा
- अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

भारत–पाकिस्तान संघर्ष विराम उर्दू प्रेस की नजर में 04
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई 09
तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का अभियान 13
उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई 16
गाजी मियां का उर्स विवादों के घेरे में 18

विश्व

बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध 21
ब्रिटेन में आतंकवाद के आरोप में सात ईरानी गिरफ्तार 23
अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध 24
पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई तेज 25
अमेरिका में कैद भारतीय शोधार्थी रिहा 26

पश्चिम एशिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तीन अरब देशों की यात्रा 27
सीरिया के नवनिर्माण की यात्रा शुरू 29
सऊदी अरब और कतर द्वारा सीरियाई कर्ज का भुगतान 32
गाजा को तीन भागों में बांटने की तैयारी 33
अमेरिका द्वारा ईरान के साथ समझौते का प्रयास 34

सारांश

भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 10 मई को अचानक घोषणा कर दी कि उनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। देश के उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुए संघर्ष विराम पर असंतोष व्यक्त किया है और यह सवाल किया है कि क्या यह समझौता किसी दबाव में किया गया है? उर्दू के अखबारों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत विरोधी रहा है और आतंकवादी संगठन उसके इशारे पर भारत में कहर ढाते रहे हैं। पाकिस्तान अनेक बार भारत सरकार को यह आश्वासन दे चुका है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसकी भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका यह आश्वासन हर बार कागजी साबित हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर लगाम लगाने की कभी कोई गंभीर कोशिश नहीं की है। कुछ अखबारों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार भारतीय सेना के शौर्य और बहादुरी का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।

हाल ही में भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस संबंध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां और पुलिस इन व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ कर रही हैं। भारत सरकार दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पहले ही देश से निष्कासित कर चुकी है।

हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खुले तौर पर पाकिस्तान को सैन्य सहायता उपलब्ध कराई है। पाकिस्तान समर्थक इन देशों की इस हरकत के कारण भारत के लोग आक्रोशित हैं। भारत के विभिन्न संगठनों ने इन दोनों देशों का बहिष्कार करने और उनके साथ व्यापारिक व पर्यटन संबंध न रखने की घोषणा की है। खास बात यह है कि ये दोनों देश मुख्य रूप से पर्यटन की आय पर ही निर्भर हैं। अगर भारतीय पर्यटक और व्यापारिक संगठन इन दोनों देशों का बहिष्कार करते हैं तो इन देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मध्य पूर्व के मामलों में सक्रिय रुचि लेनी शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का चार दिवसीय दौरा किया है। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान इन मुस्लिम देशों के साथ रक्षा उपकरणों से जुड़े अरबों रुपये के सौदे किए हैं। खास बात यह है कि ट्रम्प ने अपने इस दौरे से पहले अमेरिका के सहयोगी देश इजरायल को भी विश्वास में नहीं लिया है।

सीरिया के मामले में अमेरिकी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए एक शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि सीरिया की नई सरकार पर भविष्य में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को सीरिया के नवनिर्माण में आर्थिक सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि सीरिया पिछले पांच दशक से ईरान और रूस के समर्थन पर टिका हुआ था। पिछले 15 सालों से इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा अपने एक सहयोगी सुन्नी संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के जरिए बशर अल-असद की शिया सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेना सीरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की अगुवाई वाले विद्रोही संगठन एचटीएस का मुकाबला करने के बजाय उसके साथ मिल गई और बशर-अल-असद को अपनी जान बचाने के लिए रूस भागना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से सीरिया की नवनियुक्त सरकार का समर्थन किया है उससे इस संदेह की पुष्टि होती है कि बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह को अमेरिका का परोक्ष समर्थन प्राप्त था।

भारत–पाकिस्तान संघर्ष विराम उर्दू प्रेस की नजर में

उर्दू के अधिकांश अखबारों ने अपने संपादकीय में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है। हालांकि, इन उर्दू अखबारों ने यह भी शिकायत की है कि भारत राजनयिक स्तर पर विफल रहा है। कुछ अखबारों ने इस संघर्ष विराम के सफल होने पर भी संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर भरोसा करके बड़ी गलती की है।

रोजनामा सहारा (14 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा ने छह और सात मई की रात को भारत द्वारा पाकिस्तान पर चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' को सैन्य विजय करार देकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, 10 मई की शाम को दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के कारण यह अभियान खटाई में पड़ गया। हैरानी की बात यह है कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का श्रेय लेते हुए कहा कि यह उनकी मध्यस्थता का नतीजा है। जबकि भारत की प्रारंभ से ही यह नीति रही है कि कश्मीर या भारत-पाकिस्तान विवाद में किसी तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर युद्ध के मैदान में भारत का वर्चस्व था तो वे इतनी जल्दबाजी में संघर्ष विराम के लिए तैयार कैसे हो गए? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने न तो अमेरिका का नाम लिया, न ट्रम्प के बयान को खारिज किया और न ही यह बताया कि पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत की रणनीति क्या होगी?

हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आज का समय युद्ध का नहीं है और न ही आतंकवाद का समय है। मोदी ने जिस लहजे में यह बात की उसमें अनिश्चितता थी और उनका स्वर रक्षात्मक था। हद तो यह है कि भारत विश्व समुदाय को भी कोई मजबूत संदेश देने में विफल रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब दुश्मन देश आपके देश पर सीधा हमला करे और संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां मूकदर्शक बनी रहें तो सिर्फ वाक्यों व शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कार्रवाई की कीमत होती है। हद तो यह है कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की भी जरूरत महसूस नहीं की।

एक ओर, आतंकवाद को राष्ट्रीय एकता की परीक्षा करार दिया जा रहा था तो दूसरी ओर, सरकार ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की। क्या सरकार की यह हरकत लोकतांत्रिक पारदर्शिता के विपरीत नहीं है? भाजपा इस सैन्य कार्रवाई को देश की अंदरूनी राजनीति में चुनावी ब्रह्मास्त्र बनाने की कोशिश कर रही है। 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन और मीडिया में निरंतर बयानबाजी इस बात का प्रमाण है कि सरकार युद्ध जैसे नाजुक मौके पर भी राष्ट्रीय हित के बजाय दलगत हित को भुनाने से बाज नहीं आई। सेना का बलिदान और सैन्य सफलताएं किसी राजनीतिक पार्टी की चुनावी विरासत नहीं होती।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया ने 'मेड इन इंडिया' हथियारों की सफलता देखी है। सवाल यह है कि अगर सैन्य मोर्चे पर हमें बढ़त हासिल थी तो पाकिस्तान की हठधर्मिता अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही है? अगर हम राजनयिक मोर्चे पर मजबूत होते तो क्या अमेरिका हमें व्यापारिक बंदिश की धमकी देता? क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता? क्या एलन मस्क जैसे व्यापारिक हित रखने वाले व्यक्ति पाकिस्तान के बयान की पुष्टि करते? अगर भारत को विश्व स्तर पर एक गरिमामयी, स्वतंत्र और ताकतवर देश के तौर पर खड़ा होना है तो इसके लिए सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि राजनयिक परिपक्वता, अंदरूनी एकता और राजनीतिक सच्चाई भी जरूरी है। हमें यह याद रखना होगा कि कौमें सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और बुद्धिमता से भी अपना सर बुलंद करती हैं। जब मार्गदर्शक ही भ्रांति का शिकार हो जाए तो काफिला मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि वह मझधार में फंस जाता है।

सहाफत (14 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुए संघर्ष विराम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में आम लोगों में मायूसी साफ नजर आ रही है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं कि क्या संघर्ष विराम का फैसला अमेरिकी दबाव में किया गया है? उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम की सूचना सोशल मीडिया पर सबसे पहले दी थी। उन्होंने दावा किया था अमेरिकी मध्यस्थता से दोनों पक्ष संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी ओर, राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद और उसके सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित की गई है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की जो गुस्ताखी की थी उसका जवाब उसे दिया गया और यह संघर्ष विराम पाकिस्तान की अपील पर ही हुआ है। इससे पहले भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने दावा किया था कि हमारा लक्ष्य आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था और इसमें हमें सफलता मिली है। हालांकि, पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला समझा और वह आतंकवाद के

साथ खड़ा हो गया। अब हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) ने भी संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय सेना इस समय कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती जिसका पाकिस्तान अनुचित लाभ उठा सके। भारत का हमेशा यह रूख रहा है कि आज के युग में युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता। एक जिम्मेवार देश के रूप में भारत और उसकी सेना अच्छी तरह से जानती है कि लंबा सैन्य तनाव राष्ट्र हित में नहीं होता है, इसलिए मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस समय भारत का लक्ष्य पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादी संगठनों को तबाह करना है। दुनिया के देश शायद ही इस बात पर आपत्ति करें कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध चाहता है। मोटे तौर पर इस संघर्ष विराम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सैन्य रणनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इंकलाब (15 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को अच्छी तरह से समझा दिया है कि अगर उसकी भूमि से आतंकवादी गतिविधियां जारी रहीं तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस्लामाबाद को चेतावनी भी दे दी है कि वह यह न समझे कि 'ऑपरेशन सिंदूर' समाप्त हो चुका है। इसे फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान को सक्रिय होकर उन तत्वों को समझाना चाहिए, जिन्होंने आतंकवाद की साजिश रचने और उसे कार्यान्वित करने को अपना ओढ़ना-बिछौना बना लिया है। अगर पाकिस्तान के शासकों ने आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज किया तो भविष्य में उसके खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारत ने सीमित और सटीक कार्रवाई के जरिए यह मिसाल कायम की है कि किसी भी मामले की कितनी और कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। युद्ध जैसे हालात को कुछ दिन जारी रखकर उसे खत्म करना दोनों देशों के हित में है। इसका कारण यह है कि विश्व की राजनीति युद्ध की अनुमति नहीं देती। एक ओर, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध रूकी नहीं है। दूसरी ओर, गाजा और इजरायल के बीच भी अभी तक वही स्थिति बनी हुई है, जो एक साल पहले थी।

भारत और पाकिस्तान युद्ध में होने वाले भारी खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। नई दिल्ली कुछ कम और इस्लामाबाद कुछ ज्यादा आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में युद्ध के कारण भारी आर्थिक बोझ और सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि युद्ध कहीं भी नहीं होनी चाहिए और कभी भी नहीं होनी चाहिए। आम इंसान समझ नहीं पाता कि युद्ध तबाही के अलावा कुछ नहीं लाती। इसमें जो हारता है वह तो हारता ही है और जो जीतता है वह भी हारता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ शिवाजी सरकार ने 'नागालैंड पोस्ट' में प्रकाशित अपने लेख में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 17.8 बिलियन डॉलर (1.34 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित विदेश

मामलों के फोरम के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान से संक्षिप्त पारंपरिक युद्ध लड़ता है तब भी उसे प्रतिदिन 1460 करोड़ रुपये से पांच हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

एतेमाद (13 मई) ने अपने संपादकीय में संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर यह युद्ध जारी रहता तो भारी मूल्य वृद्धि होती और दुनिया आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाती। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के बयान का समर्थन करते हुए समाचारपत्र ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को यह संदेश देने में सफल रहा है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। भारत सरकार के इस कड़े रूख के कारण ही पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ है। यह बात शत-प्रतिशत सही है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह स्वयं एक समस्या है।

मुंसिफ (13 मई) ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जिस अंदाज में संघर्ष विराम की घोषणा की है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह नहीं करवाई है, बल्कि उन्हें यह आदेश दिया है कि वे फौरन संघर्ष विराम के लिए तैयार हो जाएं। किसी को भी भनक नहीं लगी कि अमेरिका ने कब मध्यस्थता शुरू की और उसने किन शर्तों के आधार पर दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए विवश किया। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इसके साथ ही भारत सीमा पार से पाकिस्तानी हमलों को विफल बनाने में भी सफल रहा। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए भारतीय सेनाओं की कार्रवाईयों को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन संघर्ष विराम ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि, यह सवाल खटक रहा है कि हम बिना किसी शर्त के संघर्ष विराम के लिए क्यों सहमत हो गए?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि काश ऐसा होता कि युद्धविराम की घोषणा एक विदेशी राष्ट्रपति के बजाय हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते। भारत कश्मीर और पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोधी रहा है, लेकिन हम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों हो गए? देश को यह भी अहसास हुआ है कि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया उस तरह का साथ किसी भी देश ने भारत को क्यों नहीं दिया? प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब यह पूछा गया कि क्या 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है? तो एयर मार्शल एके भारती ने न तो इस दावे की पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दे दिया कि युद्ध जैसी घटनाओं में नुकसान तो होता ही है। एयर मार्शल भारती के इस संकेत से हमारी निराशा में और भी वृद्धि हुई है। इस युद्ध के कारण इस क्षेत्र में भारतीय वर्चस्व की छवि को भी भारी क्षति पहुंची है।

उर्दू टाइम्स (13 मई) ने संघर्ष विराम की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे चारों तरफ से मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। अजीब बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने

अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। हालांकि, इस घोषणा के बाद भी दोनों देशों के बीच कई स्थानों पर संघर्ष हुआ, जिसमें काफी लोग मारे गए। विपक्षी दलों और खास कर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने देश को गैरजरूरी युद्ध की आग में झोंक दिया। कांग्रेस ने मांग की है कि मोदी संसद में आकर 'ऑपरेशन सिंदूर' की विफलताओं के बारे में उठाए जा रहे सवालों का जवाब दें। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह ऑपरेशन बिना ठोस तैयारी के शुरू किया गया। इससे भारत को राजनयिक और सैन्य स्तर पर भारी क्षति उठानी पड़ी।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल करके कई चुनाव जीते हैं, लेकिन हाल का उनका कदम उल्टा पड़ा है और इससे मोदी सरकार की साख को भारी क्षति पहुंची है। अब देश की जनता मोदी से सवाल कर रही है कि अगर लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो युद्ध क्यों छेड़ा गया? यह आलोचना मोदी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा।

अखबार-ए-मशरिक (14 मई) ने अपने संपादकीय में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद पाकिस्तान के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ और न ही भारत के प्रति उसके रूख में कोई सकारात्मक बदलाव आया है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की सरपरस्ती और उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का सिलसिला बंद नहीं किया है। पाकिस्तान पहले भी कई बार यह वायदा कर चुका है कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका यह दावा सिर्फ कागजी रहा। साफ बात यह है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। फिर भारत सरकार बिना किसी शर्त के संघर्ष विराम के लिए क्यों तैयार हो गई? इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमें इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि पाकिस्तान अपनी काली करतूतों से बाज आ जाएगा, इसलिए पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में किसी तरह की नरमी नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की गतिविधियां इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा हैं।

अखबार-ए-मशरिक (12 मई) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि भारत जब भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है तो वह विश्वभर में अकेला रह जाता है। उसके साथ कोई भी देश खड़ा नहीं होता है। इस बार भी अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों के उन्मूलन के बारे में अपनी जुबान नहीं खोली। सच्चाई तो यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी नजर में पहलगाम आतंकी हमला भारत की स्थानीय समस्या है। हालांकि, यह वही अमेरिका है जो आतंकवाद की आड़ लेकर दुनिया के अनेक देशों को सैन्य कार्रवाईयों में झोंक चुका है।

यह कड़वी सच्चाई है कि जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकार की सरपरस्ती में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उनमें से कई संगठनों को अमेरिका ने

भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सहायता देकर इन आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहन देता आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ अभियान में दुनिया का सहयोग मांगा तो किसी भी देश ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब भारत और पाकिस्तान संघर्ष में उलझे हुए थे तो अमेरिका के इशारे पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को एक बिलियन डॉलर का कर्ज दे दिया। इससे निश्चित रूप से पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई है और इसकी संभावना बढ़ गई है कि पाकिस्तान इस धनराशि को आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी सेना की ताकत में वृद्धि के लिए खर्च करेगा। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की हैसियत अमेरिका के एक नौकर की तरह हो गई है। यही कारण है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए दिल खोलकर उसे हथियारों की सहायता दी है।

हिंदुस्तान (12 मई) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि भारत ने बिना किसी शर्त के अचानक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। देश के सभी विपक्षी दलों और जनता ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए भरपूर समर्थन दिया था। विपक्षी पार्टियों और जनता ने सरकार पर दबाव डाला था कि वह देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई नरमी न बरते और न ही उससे समझौता करे, लेकिन हैरानी की बात है कि मोदी सरकार ने विपक्ष और देश की जनता को विश्वास में लिए बिना पाकिस्तान के साथ अचानक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की यह घोषणा देश और विपक्ष के साथ विश्वासघात नहीं है? मोदी सरकार को चाहिए था कि संघर्ष विराम वार्ता शुरू करने से पहले वह देश की जनता व विपक्ष को विश्वास में लेती और उन्हें यह जानकारी देती कि इस समझौता वार्ता का आधार क्या है? सबसे दुख की बात यह है कि संघर्ष विराम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कर दी।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विभिन्न राज्यों की पुलिस व गुप्तचर विभाग के सहयोग से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक इस संदर्भ में लगभग दो दर्जन जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए इन जासूसों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में भारत से निष्कासित कर दिया है। उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

इंकलाब (18 मई) के अनुसार हरियाणा पुलिस ने एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार से गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के अनुसार ज्योति मल्होत्रा का संबंध दिल्ली स्थित

व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट आदि से लगातार संपर्क रखा। ज्योति ने उन्हें भारतीय सैन्य छावनियों व सैन्य गतिविधियों के बारे में अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारी दी। अदालत ने ज्योति को पांच दिनों की रिमांड पर पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। आईबी, एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों ने ज्योति से विस्तृत पूछताछ की है। उससे की गई पूछताछ के अनुसार वह तीन बार पाकिस्तान, दो बार बांग्लादेश और एक बार चीन का भी दौरा कर चुकी है। यहां पर वह इन देशों के गुप्तचरों के संपर्क में आई और उसने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया।

पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त एक अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से है। अब तक की जानकारी के अनुसार ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। गौरतलब है कि भारत सरकार दानिश को अवांछनीय व्यक्ति घोषित करके उसे पहले ही भारत से निष्कासित कर चुकी है। ज्योति मल्होत्रा से हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त एनआईए भी विस्तृत पूछताछ कर रही है। गुप्तचर विभाग काफी समय से ज्योति मल्होत्रा पर नजर रख रहा था। हरियाणा पुलिस का दावा है कि ज्योति ने यह स्वीकार किया है कि वह पिछले कई सालों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही थी। ज्योति ने आईएसआई को भारत की सैन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई थी।

पुलिस के अनुसार ज्योति 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यालय में गई थी। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश ने ज्योति की पाकिस्तान यात्रा की पूरी व्यवस्था की। पाकिस्तान में उसकी मुलाकात आईएसआई के एक अधिकारी अली अहवान से हुई। अहवान ने ज्योति के पाकिस्तान में रहने और भ्रमण करने की व्यवस्था की और उसने उसकी मुलाकात पाकिस्तान की विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारियों से करवाई। जब वह वापस भारत आई तो उसने आईएसआई के अधिकारियों से

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हरियाणा के नूंह जिले के थाना नगीना के एक गांव राजाका से एक 22 वर्षीय युवक अरमान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अरमान पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। उस पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप के जरिए देश की सैन्य गतिविधियों की जानकारी आईएसआई को दी थी। उसके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने उसे छह दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीन राज्यों की पुलिस के सहयोग से एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों ने देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा से की गई पूछताछ के अनुसार उसने 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया था। यह पासपोर्ट 2028 तक वैध है। उसके पासपोर्ट के

अनुसार वह अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, दुबई, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया समेत कई देशों का दौरा कर चुकी है। पंजाब से गिरफ्तार किए गए जासूसों में मलेरकोटला की रहने वाली गुजाला, यामीन मोहम्मद, पलक शेर मसीह, सूरज मसीह, सुनील कुमार, रकीब खान, सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह शामिल हैं। जबकि हरियाणा से गिरफ्तार किए गए लोगों में पानीपत की एक फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड नोमान इलाही, कैथल का एक स्नातकोत्तर छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों और नूंह का एक ट्रक ड्राइवर अरमान शामिल है। वहीं, जासूसी के आरोप में उत्तर प्रदेश से भी अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार की गई 51 वर्षीय गुजाला ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के निष्कासित अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पंजाब में सैन्य अड्डों से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई थी। इसके बदले में दानिश ने उसे यूपीआई के माध्यम से 30 हजार रुपये का भुगतान किया था। जबकि यामीन मोहम्मद ने भी पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां भेजी थी। इसके बदले में उसे ऑनलाइन भुगतान किया गया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की स्पेशल टास्क फोर्स ने रामपुर के एक व्यक्ति शहजाद को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि वह एक दर्जन बार पाकिस्तान जा चुका है और वह सीमा पार से विभिन्न वस्तुओं की तस्करी करता था। बाद में वह आईएसआई के संपर्क में आया। शहजाद काफी समय से आईएसआई को सैन्य महत्व की जानकारी उपलब्ध करवा रहा था। शहजाद के परिवारजनों ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी का जासूसी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान से कपड़े व अन्य वस्तुएं लाकर उन्हें रामपुर में बेचा करता था।

अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के रहने वाले पलक शेर मसीह और सूरज मसीह ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया है कि उन्होंने हाल ही में पंजाब में सैन्य गतिविधियों, सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल के शिविरों, हवाई अड्डों और अन्य महत्त्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजी। जबकि गुरदासपुर से गिरफ्तार किए गए सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और पाकिस्तान में बने हुए पिस्तौल बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों को भारतीय सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारियां दी थी। हरियाणा के पानीपत की एक फैक्ट्री में काम करने वाला नोमान इलाही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। वह पानीपत की हाली कॉलोनी में अपनी बहन और बहनोई के साथ रह रहा था। उस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी दी थी।

रोजनामा सहारा (20 मई) के अनुसार नोमान इलाही से पूछताछ के दौरान गुप्तचर एजेंसियों को कई महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है।

मिली जानकारी के अनुसार नोमान ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बना रखा था। वह आईएसआई को तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया करता था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कैराना में रहने वाले तीन अन्य मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया है। कैथल के 25 वर्षीय छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से ननकाना साहिब की धार्मिक यात्रा की थी। इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आया। उसने यह स्वीकार किया कि उसने पटियाला छावनी से संबंधित कई तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी थी।

नूंह से एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद तारीफ को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने यह स्वीकार किया है कि वह कम-से-कम तीन बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है और वहां की खुफिया एजेंसियों के कई अधिकारियों के संपर्क में है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अधिकारियों आसिफ बलूच और जफर को सिम कार्ड दी थी। सिरसा के पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि मोहम्मद तारीफ ने पाकिस्तानी सेना को सिरसा स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। इसी के आधार पर पाकिस्तान ने सिरसा एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने इस हमले को विफल बना दिया था।

जांच एजेंसियां उड़ीसा के पुरी में रहने वाली एक यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ कर रही हैं। हालांकि, अभी तक उसे हिरासत में नहीं लिया गया है। बताया जाता है कि ज्योति मल्होत्रा कई बार उसके पास रूकी थी और उसने वहां से भारतीय मिसाइलों के परीक्षण से संबंधित अनेक तस्वीरें आईएसआई को उपलब्ध कराई थी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक कम-से-कम 10 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन संदिग्ध व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भारत के वेस्टर्न कमांड और अटैकिंग कोर से जुड़ी अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 मई) के अनुसार एनआईए ने मुंबई हवाई अड्डे पर छापा मारकर दो फरार आतंकवादियों अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से बताया जाता है। इन्होंने 2023 में पुणे में एक दर्जन स्थानों पर विस्फोट किए थे। इसके बाद ये फरार हो गए थे। जबकि इस गिरोह से संबंधित एक दर्जन अन्य आरोपी इस समय जेलों में बंद हैं। एनआईए ने इन दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी

के लिए तीन-तीन लाख रुपये के ईनाम की घोषणा की थी, लेकिन ये दोनों आतंकवादी पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर इंडोनेशिया भाग गए थे। अब इंडोनेशिया से भारत वापसी पर एनआईए ने इन्हें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में ले लिया है। गुप्तचर एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं।

तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का अभियान

इंकलाब (15 मई) के अनुसार हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि उसे ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए। इसके कारण भारत में इन दोनों देशों के बहिष्कार का अभियान बड़ी तेजी से जोर पकड़ रहा है। विभिन्न संगठनों की ओर से देशवासियों से अपील की गई है कि वे इन दोनों देशों की यात्रा न करें। इसके अतिरिक्त तुर्की की वस्तुओं का भी बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते को रद्द कर दिया है। जेएनयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। देश के पांच अन्य विश्वविद्यालयों ने भी तुर्की के साथ किए गए समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के फल व्यापारियों ने भविष्य में तुर्की से सेब न मंगवाने का फैसला किया है। इसी तरह से उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स समिति ने भी तुर्की से संगमरमर न मंगवाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि तुर्की भारत को संगमरमर सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। समिति के अध्यक्ष कपिल सुराना ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि तुर्की से संगमरमर मंगवाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस फैसले से व्यापारिक दृष्टि से तुर्की को जबर्दस्त झटका लगेगा।

दूसरी ओर, मेक माई ट्रिप समेत कई ट्रैवल एजेंसियों ने भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वे अजरबैजान और तुर्की की यात्रा की योजना को

रद्द कर दें। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी अपील के कारण 60 प्रतिशत लोगों ने अपनी टिकटें रद्द करा ली हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भारतीय फिल्म उद्योग से अपील की है कि वे भविष्य में तुर्की और अजरबैजान में किसी भी फिल्म की शूटिंग न करें। मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का समर्थन करते हुए 'एक्स' पर लिखा कि अगर भारतीय पर्यटक तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करते हैं तो उन देशों को प्रति वर्ष चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा।

सहाफत (19 मई) के अनुसार नवी मुंबई के व्यापारियों ने तुर्की से सेब आयात करना बंद कर दिया है। एक फल व्यापारी विजय भेंडे ने बताया कि पिछले साल तुर्की से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सेब मंगवाए गए थे। अब तुर्की के भारत विरोधी रूख को देखते हुए व्यापारियों ने यह फैसला किया है कि भविष्य में तुर्की से किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध न रखा जाए। एक अन्य समाचार के अनुसार पुणे के ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि भविष्य में तुर्की से ड्राई फ्रूट्स नहीं मंगवाया जाएगा।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार भारत के हवाई अड्डों पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली तुर्की की कंपनी 'सेलेबी' की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है।

उर्दू टाइम्स (13 मई) के अनुसार तुर्की और अजरबैजान की कुल आय का 20 प्रतिशत हिस्सा पर्यटन से आता है। अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में 70 प्रतिशत भारतीय होते हैं। अब भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों में जाने के बजाय थाईलैंड जाना शुरू कर दिया है। कई ट्रैवल कंपनियों और एयरलाइंस ने यह भी फैसला किया है कि तुर्की और अजरबैजान का टिकट रद्द करवाने वालों से रद्दीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले साल साढ़े पांच लाख से अधिक लोगों ने इन दोनों देशों की यात्रा की थी। 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का कुल व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर था। इसमें निर्यात 6.65 बिलियन डॉलर और आयात 3.78 बिलियन डॉलर था।

चट्टान (18 मई) के अनुसार तुर्की ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो वह खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि अजरबैजान ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए जा रहे हवाई हमलों की निंदा की थी। बहिष्कार की मांग को तब बल मिला जब भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए तुर्की में बने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी समेत एक दर्जन भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है। भारत की विभिन्न कंपनियों ने पुष्टि की है कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले 90 प्रतिशत पर्यटक अपनी बुकिंग रद्द करवा चुके हैं।

रखना सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं है? अब केंद्र सरकार की नींद खुली है और वह इन दोनों देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस समय भी देश के कई बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में तुर्की की कंपनियां काम कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इन कंपनियों के साथ किए गए समझौतों को रद्द नहीं किया गया है।

इंकलाब (19 मई) के अनुसार आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की के संस्थानों से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। इस समय आईआईटी बॉम्बे के तुर्की के कई शिक्षण संस्थानों के साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं। इससे पहले आईआईटी रूड़की ने भी तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौते तोड़ लिए थे। जबकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान (17 मई) ने अपने संपादकीय में तुर्की और अजरबैजान के भारत विरोधी रूख की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब भारत का पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था तब तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन उपलब्ध कराए। इसी तरह से अजरबैजान ने भी भारत के साथ अपने पुराने संबंधों की परवाह किए बिना पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। भारत के साथ वर्षों पुराने संबंधों के बावजूद तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। देशभर में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जनाक्रोश दिन-प्रतिदिन भड़क रहा है। अजीब बात है कि देश के प्रमुख हवाई अड्डों की देखभाल की जिम्मेवारी तुर्की की एक कंपनी को दी गई थी। क्या इससे पहले किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस कंपनी को ठेका दिए जाने का विरोध किया था? क्या ऐसे मामलों पर नजर

हमारा समाज (16 मई) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि भारतीय सेना जब पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंदने पर अमादा थी तो पाकिस्तान के परंपरागत दोस्त अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को संघर्ष विराम का आदेश देकर पाकिस्तान को बचा लिया। ऐसे समय में हमारे देश के राष्ट्रभक्तों को सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए था, लेकिन आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों का सारा गुस्सा अमेरिका के बजाय तुर्की पर निकल रहा है। क्या भारतीय 'नफरती कीड़ों' को इस बात का अनुमान है कि पाकिस्तान विरोध के चक्कर में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ बैठे बैठाए पंगा लेकर अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं। टीवी स्टूडियो में बैठकर तुर्की पर टिप्पणी करना अलग बात है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि तुर्की नाटो का सदस्य है और उसने अजरबैजान की खुलकर मदद करके आर्मीनिया को हराया था। हालांकि, आर्मीनिया एक ईसाई देश है और नाटो में ईसाई देशों का बहुमत है।

रोजनामा सहारा (19 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान निशाने पर था। अब तुर्की भी भारत के निशाने पर

आ गया है, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को मिसाइल और ड्रोन उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना एक सैन्य जलपोत कराची भेजा था। तुर्की ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का समर्थन करना उसे इतना महंगा पड़ेगा। तुर्की इस साल भारतीय पर्यटकों और भारतीय फिल्मों की शूटिंग से बहुत ज्यादा धन कमाने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसे लेने के देने पड़ गए हैं।

उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई

हिंदुस्तान (14 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक 350 से अधिक मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों और ईदगाहों को सील करके ध्वस्त किया जा चुका है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार जिन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इन अवैध इमारतों में विदेशी गुप्तचर और आतंकवादी शरण लेते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी में की गई है। प्रवक्ता ने दावा किया कि प्रशासन द्वारा अवैध भवन निर्माताओं से भूमि की स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजें मांगी गई थी, लेकिन अधिकांश लोग इससे संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार का अभियान अवैध निर्माण के खिलाफ है और इसका किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है।

एतेमाद (5 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसों, मस्जिदों एवं मुसलमानों की आस्था से संबंधित भवनों के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू कर दिया गया है। दो दिन के अंदर लगभग 100 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया गया है। जबकि 250 से अधिक मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों और मस्जिदों को अवैध घोषित करके उन्हें बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई नेपाल के सीमावर्ती जिलों में की गई है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि

कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का फैसला किया गया था। इस अभियान में जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल का सहयोग लिया गया है। महाराजगंज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया कि महाराजगंज में सरकारी भूमि पर 300 से अधिक अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं। इन अवैध निर्माणों की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कई दर्जन मदरसे अतिक्रमण करके बनाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये मदरसे कई दशक पहले बनाए गए थे और उनके पास स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

कौमी तंजीम (17 मई) के अनुसार 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-नेपाल सीमा पर विदेशी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विशेष रूप से मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में रूकने वाले लोगों की बारिकी से जांच की जा रही है। यह कार्रवाई महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के गुप्तचर विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि वे विदेशी जासूसों और आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। अब तक 250 मदरसों, 40 मस्जिदों, 25 मजारों और छह ईदगाहों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जा चुका है। यह अभियान भारत-नेपाल सीमा के 100 किलोमीटर क्षेत्र में चलाया जा रहा है।

एतेमाद (15 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को परंपरागत इस्लामी दीनी शिक्षा तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर आदि विषय भी शामिल किए जाएं। इन मदरसों का नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नया पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु सामाजिक कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय राज्य में 13329 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 12 लाख 35 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 10 हजार मदरसे प्राथमिक स्तर के हैं। शेष मदरसे माध्यमिक स्तर के हैं। इनमें से 561 मदरसों को आधुनिक मदरसा योजना के तहत सरकारी अनुदान दिया जाता है।

मुंसिफ (14 मई) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इस्लाम विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अवैध निर्माण की आड़ में सदियों पुराने मदरसों का नामोनिशान मिटाया जा रहा है। समाचारपत्र ने अपील की है कि ये इस्लामी मदरसे दीन के किले हैं, इसलिए इनकी रक्षा के लिए हर मुसलमान को मैदान में उतर जाना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इन मदरसों को परंपरागत रूप से समाज के दान पर चलाया जाए और सरकार से किसी भी तरह का अनुदान न लिया जाए।

इंकलाब (21 मई) ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी मदरसों के खिलाफ अभियान में शामिल हो गया है। आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाराबंकी जिले के मदरसों के खातों की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी जिले के कस्बा जैदपुर के एक निवासी ने एनसीपीसीआर से यह शिकायत की थी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और मदरसों के प्रबंधकों की मिलीभगत से राज्य के 588 मदरसों में ऐसे सैकड़ों अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जो प्रशिक्षित नहीं हैं। यह भी शिकायत की गई है कि उत्तर प्रदेश में अनेक मदरसों के प्रबंधक सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों से गठजोड़ करके फर्जी मदरसों के लिए सरकारी अनुदान बटोर रहे हैं। हालांकि, इन कथित मदरसों के पास अपने भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार 2017 से किसी न किसी बहाने मदरसों के प्रबंधकों को परेशान कर रही है ताकि वे तंग आकर राज्य के सभी मदरसे बंद कर दें। एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इन मदरसों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच की जाय और यदि वे अपात्र पाए जाते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कामिल और फाजिल की डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसलिए यह जरूरी है कि इन मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की जांच की जाए।

गाजी मियां का उर्स विवादों के घेरे में

उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच स्थित दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी के उर्स पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रद्द कर दिया है। अब दरगाह पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा।

रोजनामा सहारा (18 मई) के अनुसार यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दरगाह कमेटी और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला प्रशासन को इस संदर्भ में दरगाह कमेटी को सहयोग देना चाहिए और उर्स के मेले में आने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दरगाह में धार्मिक और पारंपरिक रस्में आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की विशेष खंडपीठ ने प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिया है कि दरगाह गाजी मियां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सड़कों पर न रोका जाए। यह आदेश अंतरिम रूप से जारी किया गया है। बाद में इस संदर्भ में अंतिम फैसला लिया जाएगा। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और उनके तर्कों को सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अदालत ने अंतरिम आदेश दिया कि दरगाह में रस्में और अन्य गतिविधियां जारी रहेंगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने 7 मई को ऐतिहासिक 'जेठ मेले' के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद दरगाह प्रबंधक कमेटी ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

इससे पहले **रोजनामा सहारा** (4 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर और अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया था कि दरगाह हजरत सालार मसूद गाजी पर मेले के आयोजन की सिफारिश नहीं की गई है और इस संबंध में दरगाह के प्रबंधकों को सूचित कर दिया गया है। इन अधिकारियों ने कहा था कि गुप्तचर विभाग ने दरगाह पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले के बारे में देवीपाटन डिवीजन के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील और डीआईजी अमित पाठक को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में देश में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इस मेले के आयोजन की अनुमति न दिए जाने की सिफारिश की गई है। एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हर साल दरगाह गाजी मियां पर लगने वाला यह मेला एक महीने तक जारी रहता है। इस मेले में 15 लाख से अधिक हिंदू-मुसलमान शामिल होते हैं। गौरतलब है कि इस बार दरगाह गाजी मियां प्रबंध समिति ने 15 मई से मेला शुरू करने की अनुमति मांगी थी। बहराइच जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसकी मंजूरी नहीं दी थी।

इंकलाब (18 मई) के अनुसार उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद सैयद अकरम आजाद ने बताया कि अदालत ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि दरगाह में होने वाली धार्मिक और पारंपरिक रस्मों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं को आने-जाने की पूरी आजादी होगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि धार्मिक आजादी और परंपराओं का सम्मान भारतीय संविधान का बुनियादी आधार है।

इंकलाब (14 मई) के अनुसार जौनपुर के जिला प्रशासन ने गाजी मियां के मेले के आयोजन

की अनुमति दे दी है। एक अन्य समाचार के अनुसार प्रयागराज जिला प्रशासन ने भी गाजी मियां के मेले की अनुमति दे दी है।

इंकलाब (10 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले के बारे में उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सरकार ने दरगाह पर आयोजित होने वाले धार्मिक रस्मों में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। यह पाबंदी दरगाह परिसर के बाहर आयोजित किए जाने वाले मेले पर लगाई गई है, जो बुनियादी तौर पर व्यापारिक होता है। अदालत को यह भी बताया गया कि जिला प्रशासन एक महीने तक चलने वाले इस मेले के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने या सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए कोई गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। अगर इस मेले को आयोजित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे शांति व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मेले पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जनता की बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मेला मेल-मिलाप का है।

उल्लेखनीय है कि बहराइच स्थित गाजी मियां की दरगाह शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है। इस उर्स से पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 'नेजा मेला' का आयोजन किया जाता है। 18 मार्च को संभल में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संभल के एसएसपी ने कहा था कि लूटेरे और कत्लेआम करने वाले व्यक्ति की याद में हर साल लगने वाला 'नेजा मेला' इस साल नहीं लगेगा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद से लेकर बहराइच तक मेले को रोकने का अभियान शुरू कर दिया था। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सैयद सालार गाजी को 'सूफी संत' बताया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर सालार मसूद गाजी को 11वीं शताब्दी का मशहूर 'इस्लामिक संत' बताया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि वर्तमान दरगाह का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने किया था।

इतिहासकारों के अनुसार सैयद सालार मसूद गाजी कुख्यात आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था। उसने 1034 में लाहौर से बहराइच पर हमले का सिलसिला शुरू किया था। रास्ते में उसने अनेक नगरों को लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। इनमें मेरठ और बदायूं आदि जिले प्रमुख हैं। यह पहला मुस्लिम आक्रांता था, जिसने अयोध्या पर हमला करके वहां के मंदिरों को तबाह कर दिया था और हजारों हिंदू श्रद्धालुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। जब वह बहराइच की ओर बढ़ा तो चित्तौरा झील के किनारे राजा सुहेलदेव ने अन्य 21 राजाओं के साथ मिलकर उसका मुकाबला किया। इस युद्ध में सालार गाजी मारा गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बहराइच पर विजय पाने के बाद उसके मकबरे का निर्माण किया था।

बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (13 मई) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अवामी लीग का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। अब अवामी लीग बांग्लादेश के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगी। इस सरकारी आदेश के अनुसार अवामी लीग के ऑनलाइन प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि भविष्य में अवामी लीग का कोई भी नेता ऑनलाइन या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं या जनसभा को संबोधित नहीं कर सकेगा। सरकारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक विशेष ट्रिब्यूनल में अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बरकरार रखना है। प्रवक्ता के अनुसार इस बैठक में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में बनाए रखने का भी फैसला किया गया है। हालांकि, इससे पहले मार्च महीने में यूनुस सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। सरकार की इस घोषणा के बाद छात्रों ने उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया था। उनकी मांग थी कि शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके खिलाफ विशेष ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जाए। इन प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग इस्लामी छात्र शिबिर ने भी सक्रिय भाग लिया था। नेशनल सिटीजन पार्टी के अध्यक्ष नाहिद इस्लाम ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अब इस देश में स्थाई शांति स्थापित हो सकेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलाहकार परिषद की इस विशेष बैठक में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कानून में संशोधन करने की भी अनुमति दी गई है। यह न्यायाधिकरण किसी भी राजनीतिक पार्टी, उसके सहयोगी या समर्थक

समूह को राष्ट्रहित में कोई भी सजा देने की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले छात्रों के विभिन्न संगठनों ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के लिए शाहबाग चौराहे पर धरना दिया था। इस धरने में नेशनल सिटीजन पार्टी, इस्लामी छात्र शिबिर, इस्लामी आंदोलन और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी समेत एक दर्जन छात्र संगठनों ने भाग लिया था। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा होने के बाद छात्रों ने ढाका में जश्न मनाया। उग्र प्रदर्शनों को देखते हुए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और अवामी लीग के नेता मोहम्मद अब्दुल हमीद को बांग्लादेश से भागकर थाइलैंड में शरण लेनी पड़ी है। इससे पहले छात्रों ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर धरना दिया था, जिसे अब अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के बाद खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि 15 जुलाई 2024 से शुरू हुए छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश छात्र लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारी छात्रों व आम जनता पर हमले किए, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो गई। देश में अहिंसा फैलाने और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के कारण अवामी लीग, उसके सहयोगी संगठन युवा लीग और छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

सियासत (8 मई) के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया चार महीने के इलाज के बाद लंदन से ढाका पहुंच गई हैं। वे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष एयर एंबुलेंस से लंदन से ढाका पहुंची हैं। शेख तमीम ने लंदन में खालिदा जिया के रहने और इलाज का भी प्रबंध किया था। इसके साथ ही लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी वापस बांग्लादेश आ गए हैं। आशा की जा रही है कि वे बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भाग लेंगे। रहमान ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मांग की है कि देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए और दिसंबर महीने तक राष्ट्रीय चुनाव करवाने की विधिवत घोषणा की जाए। जबकि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कहना है कि नए चुनाव नए संविधान की घोषणा के बाद ही करवाए जा सकते हैं। इससे पहले चुनाव करवाना संभव नहीं होगा।

हिंदुस्तान (11 मई) के अनुसार मोहम्मद यूनुस सरकार के शासनकाल में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता में भारी वृद्धि हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस (बांग्लादेश चैप्टर) की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही यूनुस सरकार ने पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया है। इसके कारण उसके कट्टरपंथी छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर और बांग्लादेश तब्लीगी जमात की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में सक्रिय आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन की गतिविधियों में भी भारी

वृद्धि हुई है। ये संगठन बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और उनके उपासना स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कई आतंकवादी संगठनों के नेताओं को भी अपनी सरकार में शामिल किया है। आतंकवादी संगठन हिज्ब उत-तहरीर के संस्थापक सदस्य नसीमुल गनी को बांग्लादेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह से जमात-ए-इस्लामी के एक कट्टरपंथी नेता मोहम्मद महफूज आलम को भी मंत्री बनाया गया है। नई सरकार ने बांग्लादेश की जेलों में बंद अनेक कुख्यात आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया है। इसमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी भी शामिल है। रहमानी के खिलाफ एक दर्जन हिंदू ब्लॉगरों की हत्या का मुकदमा चल रहा था। नई सरकार ने यह मुकदमा वापस ले लिया है। नई सरकार के कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता आसिफ नजरुल ने लश्कर-ए-तैयबा के बांग्लादेश प्रमुख हारुन इजहार से भी मुलाकात की है।

ब्रिटेन में आतंकवाद के आरोप में सात ईरानी गिरफ्तार

रोजनामा सहारा (6 मई) के अनुसार ब्रिटिश पुलिस ने आतंकवाद के आरोप में सात ईरानी नागरिकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। **ब्रिटेन** की गृह मंत्री इवेट कूपर ने कहा है कि ये ईरानी नागरिक देश में अनेक स्थानों पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां पश्चिमी लंदन, स्विंडन, स्टॉकपोर्ट और मैनचेस्टर से की गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोग देश में कुछ स्थानों पर आतंकवादी हमले करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इन हमलों के लिए विस्फोटक पदार्थ और हथियार भी जुटाए थे। इन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन पर जासूसी करने और देश में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप है। कूपर ने कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इस संदर्भ में अभी विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है। अभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। कूपर ने कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार जिन सात ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है उनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से होने की पुष्टि हो चुकी है।

रोजनामा सहारा (20 मई) के अनुसार ईरान ने अपने नागरिकों की गिरफ्तारी पर चिंता प्रकट की है। इस संबंध में तेहरान स्थित ब्रिटिश राजदूत को बुलाकर विरोध प्रकट किया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'आईआरएनए' के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने इन ईरानी नागरिकों को राजनीतिक कारणों से झूठे आरोपों में गिरफ्तार

किया है। जबकि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि जिन ईरानी नागरिकों को पकड़ा गया है वे अगस्त 2024 में अवैध रूप से ब्रिटेन में दाखिल हुए थे।

अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध

कौमी तंजीम (13 मई) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देशभर में शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह खेल भाग्य पर विश्वास को बढ़ावा देने वाला और इस्लामी शरिया के खिलाफ है, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में खेल विभाग के प्रवक्ता अटल मशवानी ने कहा कि शरिया कानून के अनुसार शतरंज को जुआ माना जाता है और तालिबान सरकार शरिया का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है। मशवानी ने कहा कि पिछले साल घोषित सद्‌गुण प्रचार और दुराचार निवारण कानून के अनुसार देश में किसी भी तरह का जुआ खेलना प्रतिबंधित है। दूसरी ओर, काबुल स्थित एक कैफे के मालिक अजीजुल्लाह गुलजादा ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' को बताया कि सरकार ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाने का जो कारण बताया है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर के इस्लामी देशों में शतरंज खेलने का चलन है और किसी भी देश में इसे इस्लाम या शरिया के खिलाफ नहीं माना गया है। गुलजादा ने कहा कि शतरंज के खेल में धनराशि की शर्त लगाने की कोई परंपरा नहीं है। लोग मन बहलाने के लिए शतरंज खेलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से अफगान निवासियों को निराशा हुई है।

गौरतलब है कि 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया था। हाल ही में उत्तरी अफगानिस्तान में संगीत वाद्ययंत्र बजाने और गाने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा है कि संगीत और वाद्ययंत्र इस्लामिक शरिया के खिलाफ हैं, इसलिए अफगानिस्तान में वाद्ययंत्रों की बिक्री और उन्हें बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछले साल तालिबान सरकार मार्शल आर्ट और उससे संबंधित प्रतियोगिताओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। महिलाओं के नौकरी करने और उनकी उच्च शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के पार्कों में जाने और वाहनों में अकेले सफर करने की अनुमति नहीं है।

पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई तेज

उर्दू टाइम्स (10 मई) के अनुसार पाकिस्तान में बलूचों की आजादी की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक दर्जन चौकियों पर कब्जा कर लिया है और इस कार्रवाई में 70 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत सरकार से मांग की है कि वह आजाद बलूचिस्तान को मान्यता देने के अतिरिक्त नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति दे।

उर्दू टाइम्स (9 मई) के अनुसार बीएलए ने लाहौर के बाद अब कराची में भी कई धमाके किए हैं। कराची में शराफी गोथ के नजदीक तीन धमाकों की आवाज सुनी गई है। मलीर जिला के एसएसपी ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से मिली सामग्री से पुष्टि हुई है कि ये धमाके रिमोट कंट्रोल के जरिए किए गए हैं। इससे पहले बीएलए ने लाहौर हवाई अड्डे पर एक सैन्य वाहन पर हमला किया था। इस हमले में 12 पुलिसकर्मियों के मरने की पुष्टि हुई है। 'जियो न्यूज' के अनुसार बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के वाहन पर किए गए हमले में आईईडी का इस्तेमाल किया था।

चट्टान (7 मई) के अनुसार बलूचों ने पिछले नौ दिनों से क्वेटा से लाहौर जाने वाली सड़क पर धरना दे रखा है। धरना देने वालों की एक नेता शगुफ्ता बलोच ने बताया कि उन्हें इसलिए धरना देना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 10 बलूचों का अपहरण करके उन्हें बंधक बना रखा है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम यह मानते हैं कि हमारे धरने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे बेटे और भाई कई सालों से लापता हैं। पाकिस्तानी सेना ने डॉ. महरंग बलोच और बलूच यकजेहती समिति के कई लोगों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर रखा है।

चट्टान (8 मई) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि बीएलए ने बलूचिस्तान के जिला कछी में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर हमला करके सात सैनिकों की हत्या कर दी है। मरने वालों में सूबेदार उमर फारूक (कराची), नायक आसिफ खान (करक), सिपाही तारिक नवाज (लक्की मरवत), नायक मशकूर अली (ओरकजई), सिपाही वाजिद अहमद फैज (बाग), सिपाही मोहम्मद असीम (करक) और सिपाही मोहम्मद काशिफ खान (कोहाट) शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के इशारे पर आतंकवाद की ज्वाला भड़काने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

कौमी तंजीम (13 मई) के अनुसार पेशावर के चमकनी पुलिस थाने के रिंग रोड़ पर पुलिस के एक वाहन पर हमला किया गया। इस हमले के पीछे खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आतंकवादियों का हाथ बताया जाता है। इस हमले में दो पुलिसकर्मी मारे गए। जबकि तीन घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इस हमले की निंदा की है।

उर्दू टाइम्स (6 मई) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा की एक दर्जन मस्जिदों के इमामों ने घोषणा की है कि कोई भी पश्तून पाकिस्तानी सेना को सहयोग न दे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अपने ही मुसलमानों पर बमबारी करती है।

अमेरिका में कैद भारतीय शोधार्थी रिहा

सूरी के वकील हसन अहमद ने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन बदर खान को इसलिए अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी फिलिस्तीनी मूल की है। हालांकि, वह अब अमेरिकी नागरिक है और यह दंपत्ति इजरायल के प्रति अमेरिकी नीति के खिलाफ देश में माहौल बना रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत में बदर खान की पत्नी माफेज सालेह पर आरोप लगाया था कि उसका हमास से सीधा संपर्क है, लेकिन सरकार इस आरोप को साबित करने हेतु अदालत में कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर सकी।

इंकलाब (16 मई) के अनुसार अमेरिकी अदालत के निर्देश पर भारतीय मूल के शोधार्थी बदर खान सूरी को टेक्सास के आव्रजन हिरासत केंद्र से मुक्त कर दिया गया है। बदर खान सूरी को 17 मार्च 2025 को हमास के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि सूरी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए वकील ने अदालत में बताया था कि अमेरिकी प्रशासन ने बदर खान सूरी का वीजा गैर-कानूनी तरीके से रद्द कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सूरी की हिरासत और उसके वीजा को रद्द करके उसे अमेरिका से निष्कासित करने का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए उसे अमेरिका से निष्कासित करने के फैसले को रद्द किया जाए। 'फॉक्स न्यूज' के अनुसार होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अदालत में यह आरोप लगाया था कि सूरी हमास के पक्ष में प्रचार कर रहा था और यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना भड़का रहा था। इसके अतिरिक्त सूरी का हमास के अनेक नेताओं से गहरा संपर्क है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है।

गौरतलब है कि बदर खान सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के अलवलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग विभाग में पोस्टडॉक्टरल फेलो है। बदर खान ने 2020 में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। अमेरिकी प्रशासन ने सूरी के खिलाफ अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत कार्रवाई की थी। इस कानून में यह व्यवस्था है कि अगर प्रशासन यह महसूस करे कि किसी भी विदेशी नागरिक की अमेरिका में मौजूदगी देश की विदेश नीति के खिलाफ है तो उसे अमेरिका से निष्कासित किया जा सकता है। इसी नीति के तहत कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र और फिलिस्तीनी कार्यकर्ता महमूद खलील को अमेरिका से निष्कासित करने का फैसला किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन का आयोजन किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तीन अरब देशों की यात्रा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही पश्चिम एशिया एवं अरब देशों में रुचि लेनी शुरू कर दी है। उन्होंने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के अपने दौरे के दौरान अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण से संबंधित समझौते किए हैं। उनके साथ अमेरिका के विभिन्न विभागों के मंत्री भी थे।

औरंगाबाद टाइम्स (19 मई) के अनुसार अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने अमेरिका द्वारा अरब देशों को हथियारों की बिक्री से संबंधित समझौते की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये सौदे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके परिवारजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। गौरतलब है कि 15 मई को कई डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में दो प्रस्ताव पेश किए हैं। इन प्रस्तावों में जोर दिया गया है कि अमेरिका द्वारा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ किए गए हथियारों के सौदे को रद्द किया जाए। एक विपक्षी सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प पुराने जमाने के बादशाहों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए विदेशी सरकारों द्वारा उन्हें अरबों डॉलर के लक्जरी विमान तोहफे में दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कतर ने ट्रम्प को 3400 करोड़ रुपये मूल्य का बोइंग 747-8 विमान तोहफे में पेश किया है। यह किसी भी विदेशी सरकार द्वारा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पदाधिकारी को दिया जाने वाला सबसे महंगा तोहफा है।

उर्दू टाइम्स (14 मई) के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह अमेरिका द्वारा अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सहयोग समझौता है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब को सी-130 परिवहन विमान, अत्याधुनिक मिसाइल, रडार सिस्टम और अन्य हथियार दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब को पांच क्षेत्रों में हथियार और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने ऊर्जा, रक्षा, खनन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका सऊदी अरब को

हवाई और मिसाइल हमले से बचने के लिए वायु रक्षा प्रणाली भी उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा सऊदी अरब की नौसेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है और सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके इस दौरे से सऊदी अरब में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।

इंकलाब (16 मई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सऊदी अरब दौरे के बाद कतर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आशा व्यक्त की है कि ट्रम्प का यह दौरा कतर और अमेरिका के संबंधों को नई बुलंदी पर ले जाएगा। दोनों नेताओं ने 243.5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के आर्थिक सौदों की भी घोषणा की। इसमें कतर एयरवेज को बोइंग विमान और जीई एयरोस्पेस इंजन की ऐतिहासिक बिक्री भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अमेरिका कतर को एमक्यू-9बी ड्रोन भी उपलब्ध कराएगा।

कौमी तंजीम (17 मई) के अनुसार अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 200 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एतिहाद एयरवेज ने अमेरिका से 28 बोइंग 787 और 777एक्स विमानों को खरीदने की इच्छा जताई है। इन विमानों का मूल्य 14.5 बिलियन डॉलर है। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा किया।

एतेमाद (15 मई) ने अपने संपादकीय में आशा व्यक्त की है कि ट्रम्प के इस दौरे से गाजा समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रम्प ने 2017 में भी सऊदी अरब का दौरा किया था। ट्रम्प ने यह आशा व्यक्त की है कि 'अब्राहम समझौते' के तहत सऊदी अरब भी इजरायल को मान्यता देगा। समाचारपत्र ने लिखा है कि इससे पहले ट्रम्प के प्रयास से चार अरब और दो अफ्रीकी देशों के साथ इजरायल के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को पहले ही इजरायल को मान्यता दे चुके हैं। सऊदी अरब ने अभी तक इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। हालांकि, अमेरिका उस पर दबाव डालता आ रहा है। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने स्पष्ट किया था कि अगर इजरायल स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार कर लेगा तो सऊदी अरब भी इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार करेगा। समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब अब यह महसूस कर रहा है कि वह और अधिक समय तक तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए उसने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया है।

चट्टान (15 मई) ने आलोचना की है कि ट्रम्प को खुश करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने बाल लहराती हुई लड़कियों का

परंपरागत नृत्य पेश किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खाड़ी के देश ट्रम्प को खुश करने के लिए हर परंपरा की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हिंदुस्तान (14 मई) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि ट्रम्प ने अरब देशों का दौरा करके यह साबित कर दिया है कि उनकी नजर में इजरायल से ज्यादा महत्व सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन का है। यही कारण है कि ट्रम्प ने अपने हालिया दौरे में इजरायल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कुछ दिनों पहले ट्रम्प ने इजरायल को यह धमकी दी थी कि अगर उसने हमास के साथ समझौता नहीं किया तो अमेरिका इजरायल को अकेला छोड़ देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका इजरायल का इस तरह से अपमान करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब इजरायल को हाशिए पर रखकर अरब देशों के साथ नए संबंधों की शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुराने राष्ट्रपति की नीतियों को नजरअंदाज करके ईरान के साथ समझौता करने हेतु गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सियासत (15 मई) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने का संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यह सुझाव दिया है कि सऊदी अरब को अब पेट्रोल पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकल्प की तलाश करनी चाहिए और ऊर्जा व खनिज के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सऊदी अरब के लिए यह महत्त्वपूर्ण अवसर है कि वह अमेरिका के सहयोग से अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप प्रदान करे।

सीरिया के नवनिर्माण की यात्रा शुरू

हिंदुस्तान (17 मई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के अनुरोध पर अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने टेलीविजन पर भाषण देते हुए कहा कि सीरिया के सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। अब सीरिया जंग का मैदान नहीं बनेगा। हम अपनी कौम को विभाजित नहीं होने देंगे। सीरिया देश के सभी नागरिकों का है, चाहे उनका संबंध किसी भी संप्रदाय से हो। उन्होंने कहा कि अरबी जनता

अब हमारे साथ है। हम बंद दरवाजे खोलने में सफल हुए हैं और अरब जगत व पश्चिमी देशों के साथ हमारे सामरिक संबंधों की शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश हो।

सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार रियाद में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा भी शामिल हुए। इस बैठक में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के अतिरिक्त तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सऊदी अरब से कतर रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका द्वारा सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने से मध्य पूर्व में स्थिरता आएगी और वहां के लोगों को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ट्रम्प ने कहा कि अहमद अल-शरा से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है और वे एक ताकतवर शख्सियत हैं।

अवधनामा (15 मई) के अनुसार सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का जबर्दस्त स्वागत किया गया और जश्न मनाया गया। ट्रम्प ने रियाद में पूंजी निवेश से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सीरिया में अधिक-से-अधिक अमेरिकी पूंजी निवेश हो ताकि सीरिया विकास की ओर अग्रसर हो सके।

हिंदुस्तान (15 मई) के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने 'अरब न्यूज' को बताया कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा से राहत मिली है। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन प्रतिबंधों को हटाने में तुर्की के राष्ट्रपति का महत्त्वपूर्ण हाथ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला सीरिया के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। कतर ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा का स्वागत किया है। इसके अतिरिक्त लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने भी यह आशा व्यक्त की है कि अमेरिका के इस फैसले से सीरिया के नवनिर्माण के नए अध्याय की शुरुआत होगी।

अवधनामा (13 मई) के अनुसार तुर्की की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। प्रतिबंधित संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) ने घोषणा की है कि वह तुर्की के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर रहा है। गौरतलब है कि कुर्दों की जनसंख्या तीन करोड़ से भी अधिक है। कभी वे ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र की सीमाओं का जिस तरह से पुनर्निर्धारण किया उससे कुर्द तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के बीच विभाजित हो गए। कुर्द मुख्य रूप से सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं। पिछले 50 सालों से वे स्वतंत्र कुर्दिस्तान देश के गठन के लिए संघर्षशील हैं। पीकेके का गठन 1978 में किया गया था। 1990 में इस संगठन ने घोषणा की थी कि वह तुर्की के अंदर आजाद कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए संघर्ष करेगा। इसके बाद तुर्की की सेना और कुर्दों के

लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद सीरिया में जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा है कि अब सीरिया के नवनिर्माण की नई शुरुआत होगी। हालांकि, यह वही अमेरिका है जिसने बशर अल-असद सरकार का तख्ता पलटने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया था।

बीच खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। तुर्की ने 1999 में इस संगठन के प्रमुख नेता अब्दुल्ला ओकलान को गिरफ्तार करके एक द्वीप में कैद कर दिया। हाल ही में ओकलान ने तुर्की के साथ स्थाई युद्धविराम की घोषणा की है। पीकेके को तुर्की के साथ-साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। कहा जाता है कि कुर्द सैनिकों को बशर अल-असद और रूस का परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। कुर्द न्यूज एजेंसी 'एएनएफ' द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीकेके ने अपने सम्मेलन में यह तय किया है कि अब कुर्द युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएंगे और इस संदर्भ में तुर्की सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 मई) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। अमेरिका ने सीरिया पर ये पाबंदियां तब लगाई थी जब सीरिया की सत्ता रूस के समर्थन पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि सऊदी अरब के दबाव पर अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरिया पर दबाव डाला है कि वह इजरायल को मान्यता दे दे।

मुंसिफ (17 मई) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि अमेरिका द्वारा सीरिया पर

उल्लेखनीय है कि 54 साल पहले शिया नेता हाफिज अल-असद ने सेना की सहायता से सीरिया की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उनके निधन के बाद सत्ता की बागडोर उनके बेटे बशर अल-असद ने संभाली। सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल-जुलानी उर्फ अहमद अल-शरा 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुए थे। उनके पिता सऊदी अरब में पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 1989 में उनका परिवार सीरिया आ गया। 2003 में अहमद अल-शरा इराक चले गए और वे वहां पर अलकायदा में शामिल हो गए। 2006 में अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पांच साल अमेरिकी जेल में बिताने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वे कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने अपना नया संगठन अल-नुशरा फ्रंट का गठन किया।

अहमद अल-शरा ने 2013 में यह घोषणा की कि उनका आईएसआईएस से कोई संबंध नहीं है। 2016 के अंत में उन्होंने अपना एक नया संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का गठन किया। उन्होंने घोषणा की कि वे ईरान और रूस की कठपुतली बशर अल-असद सरकार का तख्ता पलटने के लिए सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस संगठन के पीछे अमेरिका और तुर्की का हाथ था। हैरानी की बात

है कि सुन्नी संगठन एचटीएस की सेनाओं का मुकाबला करने के बजाय बशर अल-असद की सेना ने उसका दामन थाम लिया। इस पूरे घटनाक्रम से रूस और ईरान दोनों को गहरा झटका लगा, क्योंकि बशर अल-असद की सत्ता इन दोनों देशों की सहायता पर ही टिकी हुई थी। बशर अल-असद सीरिया से भागकर रूस चले गए और अभी वे वहीं पर रह रहे हैं।

सबसे रोचक बात यह है कि पांच महीने पहले जिस संगठन एचटीएस ने बशर अल-असद सरकार का तख्ता पलटा उसके प्रमुख अहमद अल-शरा को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित करके उन पर 10 मिलियन डॉलर इनाम की घोषणा कर रखी थी। अहमद अल-शरा के सत्ता में आने के बाद अब अमेरिका ने भी अपना रंग बदल लिया है और उसने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का दामन थाम लिया है। ■

सऊदी अरब और कतर द्वारा सीरियाई कर्ज का भुगतान

इंकलाब (18 मई) के अनुसार विश्व बैंक ने घोषणा की है कि सऊदी अरब और कतर ने सीरिया पर बकाया कर्ज 15.5 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है। अब सीरिया विश्व बैंक से फिर से कर्ज ले सकता है। सीरिया 14 साल के बाद विश्व बैंक की सहायता से अपनी विकास योजनाओं को फिर से शुरू कर सकता है। विश्व बैंक के रवैये में यह परिवर्तन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा के बाद आया है। ट्रम्प ने सऊदी अरब में घोषणा की थी कि अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सीरिया में गृहयुद्ध के खात्मे के बाद अभी तक बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक बयान में कहा है कि सीरिया की 90 प्रतिशत जनता गरीबी के स्तर से भी नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। देश में प्रतिदिन औसतन एक से डेढ़ घंटे बिजली सप्लाई की जाती है। करोड़ों सीरियाई लोग व्यक्तिगत जेनरेटर या सोलर पैनल खरीदने में सक्षम नहीं हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में उन्होंने इजरायल से कोई विचार-विमर्श नहीं किया है। अमेरिकी वेबसाइट 'एक्सक्लूसिव' ने दावा किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रम्प से अनुरोध किया था कि वे सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा न करें। इसके बावजूद ट्रम्प ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा करने से पहले न तो इजरायल को विश्वास में लिया और न ही उसे यह जानकारी दी कि वे सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से सऊदी अरब में मुलाकात करने वाले हैं। ■

गाजा को तीन भागों में बांटने की तैयारी

इंकलाब (20 मई) के अनुसार हाल ही में गाजा पर इजरायली हमलों में तेजी आई है। इजरायल हमास पर दबाव डाल रहा है कि वह नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जाए। इजरायल गाजा को तीन भागों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इन तीनों भागों के आसपास इजरायली सेना के तीन अड्डे होंगे। इजरायल इन इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनियों की सख्त निगरानी करेगा और उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्रिटिश अखबार 'द संडे टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार गाजा के उत्तर, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में इजरायली सेना की छावनियां होंगी ताकि वहां के फिलिस्तीनियों की कड़ी निगरानी की जा सके। इन तीनों क्षेत्रों में आवागमन करने के इच्छुक लोगों को विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। इजरायली सेना की कड़ी जांच के बाद ही इन क्षेत्रों में खाने-पीने और राहत का अन्य सामान ले जाने की अनुमति होगी। इस उद्देश्य से दक्षिण और मध्य गाजा के बीच एक सैन्य गलियारे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक बफर जोन भी बनाया जाएगा।

बताया जाता है कि इस योजना को अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस समाचार पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है। दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली सेना गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने हेतु कटिबद्ध है। न्यूज एजेंसी 'अल अरेबिया' के अनुसार महिलाओं के वेश में इजरायली सेना का एक विशेष दस्ता गाजा के शहर खान यूनिस में दाखिल हुआ था। इस दस्ते का लक्ष्य हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को मुक्त कराना था, लेकिन उन्हें अपनी योजना में सफलता नहीं मिली। कुछ सुरंगों की तलाशी ली गई, लेकिन वहां पर कोई बंधक मौजूद नहीं पाया गया।

एतेमाद (15 मई) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव के नजदीक बेन गुरियन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यह हमला इजरायल की ओर से गाजा पर किए जा रहे हमलों के जवाब में किया गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 मई) के अनुसार कतर में एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की है कि अमेरिका गाजा पट्टी को 'मुक्त क्षेत्र' बनाने हेतु तैयार है, क्योंकि अब गाजा में बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने गाजा की तस्वीरें देखी हैं। वहां पर कोई इमारत बची हुई नहीं है। लोग मलबे के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि गाजा को एक 'मुक्त क्षेत्र' बनाया जाए। इस संबंध में हम हमास से भी बातचीत कर रहे हैं।

एतेमाद (9 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गाजा पर कब्जा करने और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की इजरायली योजना से फिलिस्तीनी जनता बेहद परेशान है। इजरायल हमास के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान की शुरुआत कर चुका है। उसका लक्ष्य गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प दोहरी नीति पर चल रहे हैं। एक ओर तो वे दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे गाजा में स्थाई शांति चाहते हैं। वहीं, दूसरी ओर वे इजरायल को परोक्ष रूप से प्रेरित कर रहे हैं कि वह गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। अभी तक हमास इजरायल के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। इजरायल की योजना है कि गाजा के निवासियों को दक्षिण की ओर धकेला जाए और उनका हमास से संपर्क काट दिया जाए। इजरायल यह प्रयास कर रहा है कि राहत टीमें गाजा की जनता तक न पहुंच पाएं ताकि भूख व प्यास से तंग आकर हमास और गाजा की जनता इजरायल के सामने आत्मसमर्पण कर दे।

कौमी तंजीम (16 मई) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि गाजा में युद्धविराम हेतु दोहा में बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 'अल अरेबिया' से बातचीत करते हुए कहा कि यह अमेरिका के हित में है कि गाजा में युद्ध समाप्त हो। हम इजरायल और हमास पर दबाव डालने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि युद्ध का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे इजरायल के लिए खुले हुए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रहित के सामने इजरायल का भी महत्व नहीं है। दूसरी ओर, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने अमेरिकी टेलीविजन चैनल 'सीएनएन' को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हाल ही में जिस तरह से इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं उससे ऐसा लगता है कि इजरायल की युद्धविराम वार्ता में कोई रुचि नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री के उस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल की युद्धविराम में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने इस बयान को उत्तेजनात्मक और गैर-जिममेवार करार दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि कतर जानबूझकर मामले को और पेचीदा बनाने का प्रयास कर रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान के साथ समझौते का प्रयास

इंकलाब (16 मई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कतर की राजधानी दोहा में कहा है कि अमेरिका बाइडेन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण मध्य पूर्व को खो चुका था, इसलिए हमने उन नीतियों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। हम मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों का संरक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम ईरान के साथ समझौते के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। ट्रम्प ने कहा कि उनके दौरे के कारण अमेरिका और सऊदी अरब के बीच नए संबंधों की शुरुआत हुई है। ईरान की चर्चा करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ एक स्थिर शांति समझौता करने हेतु काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक सीमा तक इस प्रस्तावित समझौते की शर्तों पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए हम ईरान की समस्या को अहिंसक और बुद्धिमतापूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं।

यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हूतियों ने इजरायल पर हमलों का सिलसिला जारी रखा तो फिर हमें भी उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर मजबूर होना

पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा ले तो ईरान न केवल परमाणु बम बनाने का विचार छोड़ देगा, बल्कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए स्थगित भी कर देगा। उन्होंने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को अपने परमाणु विकास केंद्रों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नहीं रहा है। हम केवल नागरिक कार्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने के पक्ष में हैं। समाचारपत्र के अनुसार एक ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के साथ समझौते का संकेत दिया है। जबकि दूसरी ओर, अमेरिका ने ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये प्रतिबंध 12 संस्थानों पर लगाए गए हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनका संबंध ईरान और चीन से है।

रोजनामा सहारा (14 मई) के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने तीन ईरानी नागरिकों और एक संस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे फारसी संक्षिप्त नाम 'एसपीएनडी' से जाना जाता है। इसे 'अमाद परियोजना' के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा है कि जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे व्यापक पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के विकास में सक्रिय भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के परमाणु ढांचे को खत्म करने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर उसकी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण किया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के सभी अड्डे ईरानी मिसाइल के निशाने पर हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा है कि अगर किसी ताकत ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ताकत से डरने वाले नहीं हैं और अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

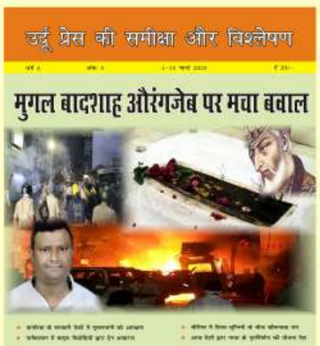

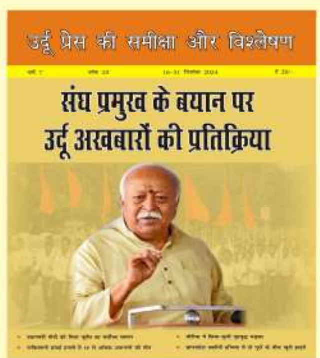

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in